टी. एस. दास और अन्य

बनाम

भारत का संघ और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 2147/2011)

27 अक्टूबर, 2016

[टी.एस. ठाकुर, सी.जे.आई, ए.एम.खानविलकर और डॉ.डी.आई.चंद्रचूड़,जे.जे.]

सशस्त्र बलः

नौसेना अधिनियम, 1957-नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964-शासन 92,95-आरक्षित पेंशन और विशेष पेंशन-अनुदान-भारतीय नौसेना में नाविकों के रूप में नियुक्त आवेदक 03.07.1976 से पहले-इस आशय का नियुक्ति पत्र कि आवेदक जो. ओ. वर्ष की सक्रिय सेवा और उसके बाद जो. ओ. वर्ष की बेड़े की सेवा में लगे हुए हैं, यदि आवश्यक हो-आवेदक सक्रिय सेवा में I0 वर्ष की प्रारंभिक अवधि से परे एक संक्षिप्त अवधि के लिए जारी रहे-इस बीच, सरकारी नीति दिनांक 03.07.1976 के कारण बेड़ा आरक्षित सेवा को बंद करना-आवेदकों को बेड़ा आरक्षित सेवाओं का मसौदा तैयार किए बिना छुट्टी दे दी गई और उपदान का भुगतान किया गया-न्यायाधिकरण के समक्ष विशेष पेंशन और आरक्षित पेंशन के अनुदान के लिए आवेदकों का दावा-न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार-एक अन्य आवेदन में न्यायाधिकरण ने ग्राम के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को स्वीकार कर लिया1957 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों में यह सुझाव देने का कोई प्रावधान नहीं है कि फ्लीट रिजर्व सेवा में ऐसे नाविकों का मसौदा तैयार करना उनकी सक्रिय सेवा/नामांकन अवधि समाप्त होने के बाद "स्वचालित" था-सरकारी नीति का प्रभाव रिजर्व फ्लीट सेवा की स्थापना को भंग करना है-रिजर्व फ्लीट सेवा में नाविकों का मसौदा तैयार करना सक्षम प्राधिकरण द्वारा किए

जाने वाले एक स्पष्ट आदेश पर निर्भर था-नाविकों को रिजर्व फ्लीट सेवा में रखे जाने के लिए निहित या उपार्जित अधिकार नहीं था-इसलिए, सक्रिय सेवा में नाविकों के 110 अधिकार प्रभावित हुए या नीति के कारण छीन लिए गए-संबंधित नाविक को तैनात नहीं करने का परिणामविनियमन के तहत विशेष पेंशन।95, ऐसे नाविकों के लिए एक अलग वितरण होना, जब तक कि शासन के तहत सजा के रूप में छुट्टी न दी जाए। 279 - आर. ई. जी. एन. के संदर्भ में कोई भी आवेदक आरक्षित पेंशन का हकदार नहीं है। 92-03.07.1976 से पहले नियुक्त सभी नाविक और जिनका प्रारंभिक सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि का कार्यकाल मृत्यु हो गया है या 03.07.1976 शासन के तहत विशेष पेंशन के लिए पात्र हैं।95, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन-सेवाओं और विविध विनियमों की नौसेना औपचारिक शर्तें, 1964-विनियमन 269.

न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 नियुक्ति पत्र की शर्त को अलग में नहीं पढ़ा जा सकता है। नौसेना अधिनियम, 1957 के प्रावधानों से यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि नियुक्ति के बाद नाविक 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा अवधि पूरी करने के बाद स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व सर्विस में बने रहने का हकदार है।हालांकि, प्रावधानों से संकेत मिलता है कि 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा पूरी होने पर या संशोधित प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई अवधि अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में निर्वहन लेने का हकदार है। आवेदकों का कहना है कि किसी भी आवेदक ने आरोपमुक्त करने का विकल्प नहीं चुना।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे नाविक के रूप में सक्रिय सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद भी फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहेंगे या वास्तव में बने रहेंगे। फ्लीट रिजर्व सर्विस में संबंधित आवेदक का मसौदा तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए था।इस तरह के आदेश की अनुपस्थिति में में, नियुक्ति की सेवा की अवधि पूरी होने पर, संबंधित नाविक को

छुट्टी दे दी जाएगी।स्वीकार्य रूप से, फ्लीट रिजर्व सर्विस पर प्रतिधारण नियोक्ता का विशेषाधिकार है, जिसका उपयोग मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना है।तत्काल मामले में, हालांकि, माफी के निर्णय के कारण, फ्लीट रिजर्व सेवा को दिनांक 03.07.1976 की अधिसूचना के बीच में बंद कर दिया गया था।[पैरा 15] (564-बी-एफ)

1.2 नीति के अनुसार डीटी.03.07.1976, जुड़ाव की प्रारंभिक अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था।उसी समय नाविकों को फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरित करना बंद कर दिया गया था।प्रासंगिक प्रावधानों में से कोई भी दूरस्थ रूप से यह नहीं बताता है कि नाविक को "स्वचालित रूप से" फ्लीट रिजर्व सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया है।जबकि, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अनुबंध की सेवा की अवधि समाप्त होने में नाविक को फ्लीट रिजर्व सेवा में केवल तभी रखा जाएगा जब सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसे फ्लीट रिजर्व में ड्राफ्ट करने के लिए उस ओर से एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाता है और अन्यथा नहीं।अधिनियम की धारा 16, केवल नाविक को नियुक्ति की सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद छुट्टी लेने का विकल्प देती है। यह एक ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि संबंधित नाविक द्वारा इस तरह के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे अगले 10 वर्षों के लिए "स्वचालित रूप से" फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा।[पारस 16,17] 1566-डी-जी]

1.3 विनियम 269 इस स्थिति को मजबूत करता है कि एक नाविक की सेवाओं को "इतने लंबे समय तक आवश्यक" या "यदि आवश्यक हो" जारी रखा जाएगा।उस विनियमन के खंड (1) के दूसरे भाग में 10 साल की सेवा के लिए "यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।इंडियन फ्लीट्स रिजर्व, उसमें प्रावधानों के अधीन।[पैरा 18] [566-एच; 567-ए]

1.4. नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 के विनियमन 92 के अनुसार आरक्षित पेंशन के अनुदान के लिए सार है।प्रत्येक आई. क्यू. वर्ष की निर्धारित नौसेना और आरक्षित योग्यता सेवा को पूरा करना। केवल एक नाविक के रूप में 10 साल की सक्रिय सेवा के पूरा होने पर या उस मामले के लिए उस अवधि के बाद भी जारी रहा, लेकिन 15 साल से कम होने या आरक्षित सेवा में अर्हता प्राप्त करने पर, संबंधित नाविक आरक्षित पेंशन के विनियमन 92 के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। रिजर्विस्ट पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उसे 10 साल की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व सर्विस में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय फ्लीट रिजर्व विनियमों के विनियम 6 के संदर्भ में, अधिकार के रूप में फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है।किसी भी आवेदक को उनकी सक्रिय सेवा पूरी होने के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, न्यायाधिकरण ने 2013 के ओ. ए. सं. 83 में याचिकाकर्ताओं पक्ष में न्यायसंगत प्रतिदान और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके आरक्षित पेंशन की राहत प्रदान क्रमांक न्यायाधिकरण ने 1957 के अधिनियम में वैधानिक प्रावधानों और नाविकों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों की अनदेखी करने में स्पष्ट त्रुटि की। तथ्य यह है कि 10 साल की सक्रिय सेवा के पूरा होने पर, नाविक को 10 साल की आगे की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व सेवा में लिया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधित नाविक ने फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल होने कानूनन अधिकार प्राप्त कर लिया था या सक्रिय सेवा/जुड़ाव की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद और 10 साल के लिए फ्लीट रिजर्व सेवा पर न्यायिक रूप से बना रहा था।अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यह सुझाव दिया जा सके कि ऐसे नाविकों को उनकी सक्रिय सेवा/नामांकन अवधि की समाप्ति के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल करना "स्वचालित" था।[पैरा20) [567-सी-एच]

1.5. यह निवेदन कि यदि सरकारी नीति दिनांक 03.07.1976 सेवारत नाविकों पर लागू की जाती है, तो अनिवार्य रूप से, उनके नुकसान के लिए पूर्वव्यापी आवेदन में परिणाम स्वीकार नहीं किया जा सकता है।यह धारा 184 ए द्वारा वर्जित है। इसमें, सरकारी नीति का प्रभाव 03.07.1976 से रिजर्व फ्लीट सर्विस की स्थापना को भंग करना है।रिजर्व फ्लीट सर्विस में नाविकों का मसौदा तैयार करना स्वतः नहीं था, बल्कि मामले-दर-मामले के आधार पर उस ओर से सक्षम प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले एक स्पष्ट आदेश पर निर्भर था।नाविकों के पास रिजर्व फ्लीट सेवा में रखे जाने का कोई निहित या अर्जित अधिकार नहीं था।इसलिए, दिनांकित 03.07.1976 नीति के कारण सक्रिय सेवा में नाविकों का कोई भी अधिकार प्रभावित या छीन नहीं लिया गया था।किसी भी मामले में नाविकों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को एक साथ पढ़ने पर और यह देखने के बाद कि नाविकों को फ्लीट रिजर्व सेवा में रखना सरकार का विशेषाधिकार है; और साथ ही नाविकों को धारा 16 के संदर्भ में निर्वहन का विकल्प देने का विकल्प दिया गया था, यह नहीं समझा जा सकता है कि इस तरह के वितरण को असमान सौदेबाजी शक्ति कैसे कहा जा सकता है।संबंधित नाविक को फ्लीट रिजर्व सर्विस में नहीं रखने के परिणामस्वरूप रिजर्विस्ट पेंशन से वंचित किया जा सकता है।हालांकि, मूल आवेदक नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 के विनियम 95 के तहत विशेष पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं, जो ऐसे नाविकों के लिए एक अलग प्रावधान है, जब तक कि विनियम 279 के तहत सजा के माध्यम से छुट्टी नहीं दी जाती है।इसे ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण के समक्ष कोई भी आवेदक विनियमन 92 की शर्तों के अनुसार आरक्षित पेंशन का हकदार नहीं है।[पैरा 21,22] (568-बी-सी, ई-एच)

1.6. विनियम 95 एक विशेष प्रावधान है और नाविकों की श्रेणी तैयार करता है, जिन पर यह लागू होना चाहिए।केंद्र सरकार में ऐसे नाविकों को विशेष पेंशन देने का

विवेक निहित है, जो अपवादात्मक श्रेणी में आते हैं, पहला, ऐसे नाविक जिन्हें भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को कम करने की सरकारी नीति के अनुसार अपने कर्तव्यों से छुट्टी दे दी गई है; या दूसरा, पुनर्गठन, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी जहाज या प्रतिष्ठान को भुगतान करना पड़ता है।तत्काल मामले में विनियमन 95 का खंड (i) लागू होना चाहिए, सरकार द्वारा लिए गए नीति निर्णय की पृष्ठभूमि में दिनांक 03.07.1976।उस तारीख से, निश्चित रूप से, फ्लीट रिजर्व सेवा को बंद कर दिया गया है।इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से उक्त नीति के लागू होने के बाद भारतीय नौसेना के फ्लीट रिजर्व की स्थापना की ताकत उस हद तक कम हो जाती है। उक्त नीति के लागू होने के बाद किसी भी नाविक को फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है-क्योंकि अब स्थापना मौजूद नहीं थी और भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत उस हद तक कम हो गई थी।निर्विवाद रूप से, 03.07.1976 से पहले नियुक्त नाविकों के पास अपनी सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि की समाप्ति के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहने का विकल्प था।प्रत्येक आवेदक के संबंध में नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि को 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा और 10 साल के बाद आवश्यकता पड़ने पर फ्लीट रिजर्व सेवा के रूप में उल्लेख किया गया है।फ्लीट रिजर्व सर्विस में बने रहने का विकल्प इन आवेदकों और इसी तरह से तैनात नाविकों को विभाग द्वारा 10 साल या 15 साल की उनकी सूची अवधि समाप्त होने के बाद नहीं दिया जा सका।ऐसे नाविकों को उनकी सक्रिय सेवा/पैनल में शामिल करने की अवधि समाप्त होने पर ही छुट्टी दे दी जाती थी।इस प्रकार, भारतीय नौसेना के फ्लीट रिजर्व इस्टैब्लिशमेंट को बंद करने के कारण, नीति के संदर्भ में भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को उस हद तक कम करने में मदद मिली है।[पैरा 23] [569-बी. सी.]

1.7. अपीलकर्ता क्रमांक 36 (2011 के सीए संख्या 2147 में) क्रमांक कहा कि उन्हें विभाग द्वारा एकतरफा रूप से फ्लीट रिजर्व से छुट्टी दे दी गई थी और उस समय तक उन्हों क्रमांक संयुक्त रूप से 17 साल 1 महीना और 26 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी, जिसके कारण उन्हें पेंशन विनियमों के विनियमन 92 (2) के तहत आरक्षित पेंशन का हकदार बनाया गया था।चूँकि यह अपीलकर्ता सरकारी नीति के अस्तित्व में आने के समय सक्रिय सेवा में नहीं था और 03.07.1976 पर बेड़ा सेवा से छुट्टी पाने के दावे सक्षम प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होंगे।इस मुद्दे की जांच करना सक्षम प्राधिकारी का काम है।[पैरा 24] (569-जी-एच; 570-ए-बी)

1.8. 03.07.1976 से पहले नियुक्त सभी नाविक और जिनकी प्रारंभिक सक्रिय सेवा/सूची अवधि मृत्यु हो गई है या 03.07.1976 के बाद मृत्यु हो गई है,वे विनियमन 95 के तहत विशेष पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं, हालांकि, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।इसमें, उन्होंने अनुबंध के एक अनुभव का निर्वहन करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और फिर भी फ्लीट रिजर्व सेवा प्रभावी 03.07.1976 को बंद करने की नीति के कारण फ्लीट रिजर्व के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा मसौदा तैयार नहीं किया गया था और न ही किया जा सका था।ऐसे नाविकों के मामलों (न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदकों तक सीमित नहीं) पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा संबंधित नाविक द्वारा आवेदन की तारीख से तीन साल पहले से "विशेष पेंशन" देने के लिए तीन महीने के भीतर विचार किया जाना चाहिए और भुगतान जारी किया जाना चाहिए।[पैरा 25] [570-डी-एफ]

मामला कानून संदर्भ

1983 (2) एस. सी. आर. 165	संदर्भित	पैरा 7
2007 (10) एस. सी. आर. 1084	संदर्भित	पैरा 7

2006 (8) पूरक।एस. सी. आर. 485	संदर्भित	पैरा 7
1986 (2) एस. सी. आर. 278	संदर्भित	पैरा 7
2006 (8) पूरक।एस. सी. आर. 485	संदर्भित	पैरा 7
2009 (11) एस. सी. आर. 710	संदर्भित	पैरा 7
2007 (8) एस. सी. आर. 883	संदर्भित	पैरा 7
1997 (5) पूरक।एस. सी. आर. 433	संदर्भित	पैरा 8
2006 (1) एस. सी. आर. 1006	संदर्भित	पैरा 8
1968 एस. सी. आर. 185	संदर्भित	पैरा 8

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2147/2011

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 182/2009 मे पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.02.2010 से

साथ

सी.ए. संख्या. 8566 / 2014.

वी. गिरि, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, टी. सुशाकर, ओमानकुट्टन के. के., सी. एम. अंगड़ी, एस. एम. दलाल, आर. पी. गोयल, श्रीकांत एन. तेरदल, निशेराजेन शौंकर, गजेंद्र किची, आर. बालासुब्रमण्यम, सुश्री अनन्या मिश्रा, एम. के. मारोरिया, सुश्री आरती, एन. के. करहैल, सुश्री सुनीता गौतम, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायधीश ए.एम.खानविलकर,जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. ये अपीलें सशस्त्र एफ-ऑर्सेस ट्रिब्यूनल (दीवानी याचिका सं 2147/2011 में अपीलार्थी और दीवानी याचिका सं 8566/2014 में प्रतिवादी) के समक्ष मूल आवेदकों द्वारा दावा की गई अलग-अलग राहत से निकलती हैं, जिसमें हालांकि, विचार के लिए अतिव्यापी बिंदु शामिल हैं।इसलिए, हम इस सामान्य निर्णय द्वारा इन दोनों अपीलों का समान रूप से निपटान करना उचित समझते हैं।

2. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा 4 फरवरी, 2010 को 2009 के मूल आवेदन क्रमांक ख्या 182 में एक आदेश से 201 की दीवानी याचिका क्रमांक 2147 उद्भूत होती है। न्यायाधिकरण ने "विशेष पेंशन" के अनुदान के लिए उसमें आवेदकों के दावे को खारिज कर दिया है। सिविल अपील संख्या 8566/2014 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के 2013 के ओए संख्या 83 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के फैसले को भारत संघ द्वारा चुनौती दी गई है। उस मामले में, न्यायाधिकरण ने "आरक्षित पेंशन के लिए आवेदकों के दावे को स्वीकार कर लिया

3. मान लीजिए, दोनों मामलों में न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदकों को 1973 से पहले भारतीय नौसेना में नाविक के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित आवेदक 10 साल की सक्रिय सेवा के लिए नाविक के रूप में कार्यरत था और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर 10 साल के लिए बेड़ा आरक्षित सेवाओं में लगा हुआ था।आवेदकों को सक्रिय सेवा/जुड़ाव में 10 साल की प्रारंभिक अवधि से परे एक संक्षिप्त अवधि के लिए जारी रखा गया और उन्हें फ्लीट रिजर्व सेवाओं में मसौदा तैयार किए बिना छुट्टी दे दी गई।ट्रायस, प्रत्येक आवेदक को भारतीय नौसेना द्वारा जुलाई, 1976 के बाद उनकी सक्रिय सेवा पूरी होने पर छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें उपदान का भुगतान किया गया था।जैसे ही न्यायाधिकरण ने अधिकारियों को आरक्षित पेंशन/विशेष पेंशन देने का निर्देश देकर इसी तरह के

व्यक्तियों को राहत प्रदान की, इन आवेदकों ने भी इसी तरह की राहत के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया।

4. ओ.ए.संख्या.182/2009 (अपीलार्थी सी.ए.नं.2147/2011) में 38 आवेदकों ने शुरू में एक व्यवहार रिट याचिका संख्या. 4805/2008 के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, ताकि नौसेना (पेंशन) विनियम,1964 (यहाँ सेः "पेंशन" विनियमों के रूप में संदर्भित)।उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई, 2008 के आदेश के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को विशेष पेंशन देने के लिए उक्त आवेदकों के दावे की जांच करने का निर्देश दिया।सक्षम प्राधिकारी ने मामले की जांच के बाद 30 सितंबर 2008 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदकों के दावे को खारिज कर दिया।सक्षम प्राधिकारी ने माना कि उक्त आवेदकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति पूरी होने के बाद सेवा से छुट्टी दे दी गई थी और उन्हें फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं थी।उन्हें भेजी गई पर्ची में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था।सक्षम प्राधिकारी ने यह भी माना कि पेंशन विनियमों का विनियम 95 उक्त आवेदकों पर लागू नहीं था क्योंकि उन्हें भारतीय नौसेना की स्थापना या किसी भी पुनर्गठन की ताकत को कम करने के उपाय के रूप में लागू नहीं किया गया था।इसके बजाय, उन्हें नौमेंना अधिनियम, 1957 की धारा 16 के तहत नियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद छुट्टी दे दी गई।इसके बाद आवेदकों ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली से संपर्क किया। 182/2009 जिसे, हालांकि, 4 फरवरी 2010 को खारिज कर दिया गया था।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदकों को 10 साल की नियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद सेवा से छुट्टी दे दी गई थी।उन्हें फ्लीट रिजर्व पर तैयार करने का कोई अधिकार नहीं था।नौसेना समारोह, सेवा की शर्तों और विविध विनियमों, 1963 (इसके बाद "सेवा विनियमों की शर्तों" के रूप में संदर्भित) के विनियमन 269 पर आवेदकों द्वारा रखी गई निर्भरता को न्यायाधिकरण द्वारा इस

निष्कर्ष पर अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त प्रावधान केवल एक सक्षम प्रावधान है और संबंधित नाविक को फ्लीट रिजर्व पर मसौदा तैयार करने के लिए प्राधिकरण में निहित विवेक है।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि विनियमन 95 उन आवेदकों के मामले में लागू नहीं था जिन्हें 1 वर्ष की नियुक्ति पूरी होने के बाद सेवा से छुट्टी दे दी गई थी।तदनुसार, उक्त आवेदकों द्वारा दायर मूल आवेदन को योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया गया था।उस निर्णय के खिलाफ, सीए सं सं. 2147/211 में अपीलकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

5. भारत संघ द्वारा दायर साथी अपील में सीए. संख्या 8556/2014, हालांकि, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई ने तीन आवेदकों द्वारा दायर मूल आवेदन को स्वीकार कर लिया है।न्यायाधिकरण ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे उक्त आवेदकों को मूल आवेदन दाखिल करने से पहले तीन साल से देय सेवा पेंशन प्रदान करें, यानी 29 अक्टूबर 2009 से और सेवा ग्रेच्युटी और पेंशन को समायोजित करें।मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-उपदान (डी. सी. आर. जी.) उन आवेदकों को अवशिष्ट राशि से पहले ही भुगतान कर चुका है।न्यायाधिकरण से निपटते समय।रिजर्विस्ट पेंशन के दावे में कहा गया कि सक्रिय सेवा की समाप्ति पर, आवेदकों को सेवा की मूल नियुक्ति के अनुसार फ्लीट रिजर्व सेवा में नियुक्त किया जाना चाहिए था।इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने वाले कोच्चि की क्षेत्रीय पीठ के न्यायाधिकरण के दूसरे फैसले पर भारत संघ द्वारा रखी गई रिलायंस को न्यायाधिकरण द्वारा न्यायसंगत वादा रोकने के सिद्धांत का आह्वान करके दरकिनार कर दिया गया है।न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि तीनों आवेदक पेंशन विनियमों के विनियम 92 के अनुसार आरक्षित पेंशन के अनुदान के हकदार थे।न्यायाधिकरण ने पेंशन विनियमों के विनियमन 95 में निर्दिष्ट विशेष पेंशन प्रदान करने के लिए उक्त आवेदकों की वैकल्पिक प्रार्थना को भी इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि 3 जुलाई 1976 की सरकारी नीति के कारण

किसी भी जहाज या प्रतिष्ठान की स्थापना या पुनर्गठन की ताकत को कम करने के परिणामस्वरूप भुगतान करने के कारण, आवेदकों को फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल नहीं किया गया था।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि आवेदकों को उपरोक्त पेंशन में से केवल एक ही दी जा सकती है और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि वे सेवा पेंशन के हकदार हैं।

6. जिन आवेदकों ने नौसेना (पेंशन) विनियम,1964 के विनियमन 95 के अनुसार विशेष पेंशन का दावा किया था, उन्होंने तर्क दिया कि 3 जुलाई, 1976 की अधिसूचना के अनुसार नीति में बदलाव के कारण फ्लीट रिजर्व सेवा को बंद कर दिया गया था।इस प्रकार, विनियमन 95 के खंड (i) की शर्तों में वे विशेष पेंशन के हकदार थे।

7. मूल आवेदकों के अनुसार, उन्होंने सक्रिय सेवा में 10 साल और फ्लीट सेवा में 10 साल के लिए नौसेना के साथ सेवा करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें अपनी पेंशन योग्य सेवा यानी सक्रिय सेवा में 10 वर्ष और फ्लीट रिजर्व में 10 वर्ष पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।यहां तक कि सेवा प्रमाण पत्र के रूप में आधिकारिक दस्तावेज भी इस स्थिति को मजबूत करेगा।उनका कहना है कि यदि उन्हें सेवा की अवधि पूरी करने की अनुमति दी जाती, जैसा कि सेवा प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है, तो वे पेंशन विनियमों के विनियम 92 के संदर्भ में आरक्षित पेंशन के हकदार हो जाते।किसी भी मामले में, फ्लीट रिजर्व की स्थापना को समाप्त करके नौसेना प्रतिष्ठान के पुनर्गठन के कारण, इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से जुलाई 1976 में भारतीय नौसेना की कुल ताकत में कमी आई।फ्लीट रिजर्व सर्विस में आवेदकों का मसौदा तैयार नहीं करने का यही एकमात्र कारण था।नतीजतन, आवेदक किसी भी मामले में पेंशन विनियमों के विनियम 95 के तहत विशेष पेंशन के हकदार थे।कि 3 जुलाई 1976 के दौरान सक्रिय सेवा में सभी नाविकों को सरकारी नीति के

कारण छुट्टी दे दी गई थी, जो अन्यथा, अपने प्रारंभिक कार्यकाल के अनुसार, फ्लीट रिजर्व सेवा में स्थानांतरित होने के हकदार थे।सरकारी नीति के संदर्भ में फ्लीट रिजर्व सर्विस को समाप्त करना भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को कम करने या उस हद तक प्रतिष्ठान उत्सादन के बराबर है।डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में इस दावे पर भरोसा किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन लंबी और कुशल सेवा प्रदान करके अर्जित की जाती है और इसलिए, इसे प्रदान की गई सेवा के लिए मुआवजे का एक आस्थगित हिस्सा कहा जा सकता है। ।जुलाई 1976 की सरकारी नीति के आधार पर मूल आवेदकों को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण को अपनाने से यह पता चलता है कि उक्त नीति उन आवेदकों के मामले में भी पूर्वव्यापी रूप से लागू की गई है जो पहले से ही इस आश्वासन के साथ सेवा में थे कि वे फ्लीट रिजर्व में 10 साल और उसके बाद 10 साल तक सक्रिय सेवा में रहेंगे।3 जुलाई, 1976 की सरकारी नीति, यदि आवेदक और समान रूप से नियुक्त व्यक्तियों में लागू की जाती है, तो उनके सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदल दिया जाएगा।यह अस्वीकार्य है, जैसा कि बी. सी. पी. पी. मजदूर संघ और ए. एन. आर. बनाम बी. सी. पी. के मामले में स्पष्ट किया गया है। एन. टी. पी. सी. और अन्य एआईआर 2008 एससी 336 और भारत संघ और अन्य बनाम एशियाई खाद्य मंत्रालय (2006) 13 एससीसी 542 नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 184-ए किसी ऐसे विनियमन को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से मना करती है जो किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।यह तर्क दिया जाता है कि पेंशन विनियमों के प्रावधानों के साथ पढ़े गए सेवा विनियमों की शर्तों के विनियम 269 से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नाविक जिसने सेवा विनियमों की शर्तों में संशोधन से पहले या बाद में भारतीय नौसेना में सेवा की थी या 3 जुलाई 1976 से सरकारी नीति के लागू होने पर, पेंशन का हकदार था।तथ्य यह है कि सरकार ने फ्लीट रिजर्व सर्विस

को बंद करने का निराकृत है, इसका उद्देश्य पेंशन प्राप्त करने के लिए सक्रिय सेवा में नाविकों के हितकारी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना था।याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण का समर्थन किया है, कि न्यायसंगत वचन-निषेध के सिद्धांत वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू होंगे।आवेदकों के अनुसार, सरकार ने विनियमन 269 (1) में आने वाली "यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति की संकीर्ण व्याख्या करने के लिए एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।यदि उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो विनियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होगा।इसमें, सरकार नाविकों को रिजर्व फ्लीट सर्विस पर रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखेगी, लेकिन उन नाविकों के लिए कोई विकल्प नहीं अनुमति जो 10 साल की सक्रिय सेवा पूरी करने के बाद 10 साल तक फ्लीट सर्विस पर रहने के लिए मूल सेवा शर्तों के अनुसार संविदात्मक दायित्व से बाध्य होंगे।"यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति को दी गई व्याख्या के अनुसार सरकार को प्रदान किया गया विवेकाधिकार कंट्राप्रोफेरेंटम के सिद्धांत से प्रभावित होगा, जैसा कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रजोनाथ गांगुली (1986) 3 एससीसी 156 के मामले में असमान सौदेबाजी की शक्ति को देखते हुए देखा गया है।एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते विभाग को "यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति के संदर्भ में इस तरह के तर्क को अपनाने के लिए नहीं सुना जा सकता है।नाविकों को पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए सरकार को नहीं सुना जा सकता है।वे उस समय सक्रिय सेवा में थे जब फ्लीट रिजर्व सर्विस को भंग करने के लिए सरकारी नीति लागू हुई थी।यह कहना एक बात है कि सरकार को अपनी स्थापना को बंद करने या फिर से व्यवस्थित करने का विवेकाधिकार है, लेकिन यह नाविकों के अधिकारों, विशेष रूप से पेंशन लाभों की कीमत में नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया कि सेवा शर्तों के विनियमों और भारत फ्लीट रिजर्व के विनियमों के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट होगा कि जब नाविक 1-

0 साल की सक्रिय सेवा के बाद जारी रखने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त नहीं करेगा, तो उसके बाद उसे फ्लीट रिजर्व सेवा में ले लिया जाएगा।असंगतता, तर्क यह है कि आवेदकों को आरक्षित पेंशन प्राप्त करने का एक अर्जित और निहित अधिकार था और इसे विनियमों में संशोधन या सरकारी नीति द्वारा इसे बंद करने के लिए बहुत कम नहीं लिया जा सकता है।फ्लीट रिजर्व सर्विस।रिलायंस को भारत संघ बनाम एशियाई खाद्य उद्योग (2006) 13 एससीसी 542, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम बचन सिंह (2009) 14 एससीसी 793 और सोनिया बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी(2007) 10 एससीसी 627 के फैसलों में रखा गया है। अपीलकर्ता संख्या 36 (आई. डी. 1 में) क्रमांक अतिरिक्त रूप से निवेदन है कि उन्हें 7 फरवरी, 1950 को सीधे प्रवेश नाविक के रूप में भर्ती किया गया था और 10 वर्ष की सक्रिय सेवा के पूरा हो क्रमांक पर अनिवार्य 10 वर्ष के फ्लीट रिजर्व के दूसरे चरण के लिए फ्लीट रिजर्व में भेजा गया था।प्रत्यर्थीगण द्वारा एकतरफा रूप से उन्हें 30 मार्च 1967 को फ्लीट रिजर्व से छुट्टी दे दी गई थी।उस समय तक, उन्होंने 17 साल 1 महीना और 26 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी।पेंशन विनियमों के विनियम 92 के खंड (2) पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें अपने अनुरोध के अलावा रिजर्व बेड़े से छुट्टी दे दी गई थी और इसलिए, वे रिजर्विस्ट पेंशन के हकदार थे। इस तथ्य को कि उन्होंने जल्दी छुट्टी के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था, विभाग द्वारा अपने दिनांकित 8 मई 2014 के पत्र में स्वीकार किया गया है और फिर भी उन्हें नाविकों के समान स्थिति के विपरीत आरक्षित पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया है।

8. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से यह निवेदन जाता है कि भारतीय नौसेना में नौसेना कर्मियों की निरंतर सेवा के लिए जुड़ाव की अवधि, जिसमें भारतीय रिजर्व बेड़े में निरंतर सेवा के लिए उनके नियम और शर्तें और रिजर्विस्ट पेंशन प्रदान करने की पात्रता भी शामिल है, सेवा विनियमों की शर्तों के विनियम 268 और 269

और भारतीय फ्लीट रिजर्व विनियमों के पेंशन विनियमों के विनियम 92 और 95 और विनियम 6 द्वारा नियंत्रित होती है।चूंकि मूल आवेदकों को 3 जुलाई 1976 से पहले नाविकों के रूप में नामांकित किया गया था, इसलिए निरंतर सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर, उनकी सेवा का सौदा केवल तभी तैयार किया जा सकता है जब विनियमन 269 (1) के अनुसार भारतीय फ्लीट रिजर्व में 10 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए आवश्यक हो।लेकिन, 3 जुलाई 1976 से फ्लीट रिजर्व सर्विस बंद होने के कारण मूल आवेदकों को इंडियन फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था और न ही किया जा सकता था।भारतीय फ्लीट रिजर्व में नामांकन 1940 के फ्लीट रिजर्व अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है।यह न तो सही और न ही स्वचालित का मामला है।भारतीय फ्लीट रिजर्व विनियमों के विनियम 6 के अनुसार मूल आवेदकों द्वारा सेवा प्रमाण पत्र में प्रविष्टियों पर भरोसा किया गया था जो नामांकन के समय केवल यह इंगित करने के लिए बनाए गए थे कि एक नाविक 10 साल की सक्रिय सेवा करेगा और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो 10 वर्ष का फ्लीट रिजर्व होगा।इस तरह की प्रविष्टि नाविक पक्ष में भारतीय फ्लीट रिजर्व पर मसौदा तैयार करने का कोई अधिकार नहीं बना सकती है। मूल आवेदक द्वारा प्रस्तावित विनियम एक सक्षम प्रावधान था न कि अनुबंध की शर्त या नाविक से किया गया कोई भी वादा कि उसे अनिवार्य रूप से फ्लीट रिजर्व में शामिल किया जाएगा।नाविकों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी भी विनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।अधिकांश नाविकों ने 10 साल की सक्रिय सेवा पूरी करने के बाद छुट्टी लेने का विकल्प चुना।फ्लीट रिजर्व में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से तैयार किए गए लोगों पर विभाग द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया गया, बशर्ते इसके लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केवल ऐसे नाविक जिन्होंने विनियमन के अनुसार 10 साल की सक्रिय सेवा और 10 साल की फ्लीट रिजर्व सेवा पूरी की थी, वे न्यूनतम पेंशन के हकदार थे।3 जुलाई

1976 से फ्लीट रिजर्व के बंद होने के कारण मूल आवेदकों को फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था।नतीजतन, मूल आवेदकों को फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था 3 जुलाई 1976 से फ्लीट रिजर्व को बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप, कोई नहीं मूल आवेदकों में से कुछ रिज़र्विस्ट पेंशन के लिए पात्र थे। यह तर्क दिया जाता है कि यह दृष्टिकोण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा केस नंबर टी.ए.492/2009 (निरंजन चक्रवर्ती, पूर्व-एल/टेल नंबर 92171) द्वारा 10.02.2010 को ओ ए संख्या.84/2010 (रामचंद्रन पिल्लई) में लिया गया है। पूर्व- एसईएआई, संख्या 88568) का निर्णय 16.05.2011 को, ओ ए संख्या.42/2012 में (मंगलाप्रसाद चौबे, पूर्व-एलएस, संख्या 94834) का निर्णय 19.06.2013 को, ओ ए संख्या.08/2013 में किया गया (एक्स नेवी डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिसर एसोसिएशन और अन्य) ने 22.01.2014 को ओ ए संख्या.02/2014 (एसएस बनसुरे, पूर्व-SEAI,संख्या.84001) में 18.06.2014 को निर्णय लिया। निरंजन चक्रवर्ती के मामले में निर्णय लिया गया है। इस न्यायालय द्वारा 13 जनवरी 2014 को निर्णयित एसएलपी (सी) संख्या 19790/2001 में इसकी पुष्टि की गई इसलिए, मूल आवेदकों के खिलाफ मुद्दा समाप्त हो गया। इसलिए, चेन्नई में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ का निर्णय, जो वर्तमान अपील में विवादित है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के फैसले के खिलाफ इस अदालत द्वारा अपील खारिज हो क्रमांक के बाद पलट क्रमांक का पात्र है। दिनांक 1 फरवरी 2010 में। न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय में लागू न्यायसंगत वचन निरसन का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, मूल आवेदकों की सेवा शर्तों के संबंध में मौजूदा विनियमों में व्यक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।मूल आवेदकों को रिजर्व फ्लीट में स्थानांतरित किए जाने या उस मामले के लिए स्वचालित रूप से स्थानांतरित किए जाने के किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए नहीं सुना जा सकता है।क्योंकि, जब तक नाविक को सक्षम प्राधिकरण के एक स्पष्ट आदेश द्वारा आरक्षित बेड़े में शामिल

नहीं किया जाता है, तब तक विनियमन 92 के संदर्भ में आरक्षित पेंशन के लिए पात्रता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। न्यायसंगत वादा रद्द करने की याचिका का पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कानून के खिलाफ रोक नहीं लगाई जा सकती है (भारत संघ और अन्य बनाम डॉ. एस. बलियार सिंह (1998) 2 एससीसी 208; संघ लोक सेवा आयोग।गिरीश जयंती लाल वाघेला और अन्य (2006) 2 एससीसी 482) रिलायंस को रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ एआईआर 1967 एससी 1889 मामले में संविधान पीठ के फैसले पर भी रखा गया है।भारत संघ ने यह विचार रखा है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा के नियमों और शर्तों को सरकार द्वारा एकतरफा रूप से बदला जा सकता है और सरकारी कर्मचारी का कोई निहित या वैधानिक अधिकार नहीं है।इसके अलावा, एक सरकारी कर्मचारी की कानूनी स्थिति अनुबंध की तुलना में अधिक अक्षम है और स्थिति की पहचान सार्वजनिक कानून द्वारा लगाए गए अधिकारों और कर्तव्यों का संबंध है, न कि पार्टियों के समझौते द्वारा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल आवेदकों (सी.ए. संख्या 8556/2014 में उत्तरदाताओं) को रिजर्व सेवा के बंद होने के बाद विस्तारित अवधि के लिए नौसेना सेवा में बने रहने का विकल्प दिया गया था। लेकिन उन सभी ने अनिच्छा व्यक्त की और इसलिए उन्हें सगाई की अवधि पूरी होने पर बर्खास्त कर दिया गया। छुट्टी लेने का विकल्प चुनने के बाद, वे आवेदक किसी भी मामले में संबंधित नियमों के अनुसार पेंशन के अनुदान से राहत का दावा नहीं कर सकते हैं।पेंशन विनियमन के विनियम 95 के दायरे के संबंध में यह निवेदन जाता है कि 3 जुलाई 1976 की अधिसूचना में प्रकट सरकारी नीति का प्रभाव भारतीय नौसेना की स्थापना की शक्ति को कम करने या उस मामले के लिए प्रतिष्ठान के पुनर्गठन के लिए नहीं था।यह भुगतान करने का मामला भी नहीं था।इसमें, आवेदकों को उनकी सक्रिय सेवा के पूरा होने पर छुट्टी दे दी गई थी।भुगतान करने के मामले में, नाविकों को भारतीय फ्लीट रिजर्व के बंद होने या बंद होने के कारण सेवा के दौरान हटाने/छुट्टी

देने की आवश्यकता थी।केवल फ्लीट रिजर्व को बंद करने के कारण, प्रभावित व्यक्ति विशेष पेंशन के हकदार नहीं हो सकते हैं।केवल तभी जब इस तरह के पुनर्गठन के मे परिणामस्वरूप किसी भी जहाज या किसी भी प्रतिष्ठान को भुगतान किया जाता है, तो विनियमन 95 का खंड (ii) लागू होगा।तदनुसार, यह निवेदन जाता है कि विशेष पेंशन के अनुदान की राहत भी योग्यता से रहित है।

9. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।यह विवाद में नहीं है कि न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक 1973 से पहले नाविकों के रूप में कार्यरत थे।आयोग, नियुक्ति और नामांकन से संबंधित प्रावधान नौसेना अधिनियम, 1957 के अध्याय IV में मिला जाते हैं (जिसे इसके बाद "I957 का अधिनियम" कहा जाता है)।1957 के अधिनियम की धारा 9 में भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना आरक्षित बलों में नियुक्ति या नामांकन के लिए पात्रता का प्रावधान है। 1957 के अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित नाविकों की सेवा के नियम और शर्तें ऐसी हैं जो निर्धारित की जा सकती हैं।इसकी उप-धारा (2) में पहली बार में 10 साल की अवधि के लिए भारतीय नौसेना में एक नाविक के कार्यकाल का प्रावधान है।बाद में इसे बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया।1987 में एक और संशोधन द्वारा उक्त कार्यकाल को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। 09.09.1987. 1957 के अधिनियम की धारा 12 नाविक के रूप में नामांकन की वैधता के बारे में है यह अभिनिर्धारित करता है कि पदधारी को विधिवत नामांकित माना जाएगा और फिर वह किसी भी अनियमितता या अवैधता या किसी अन्य आधार पर अपने निर्वहन का दावा करने का हकदार नहीं होगा।अधिनियम 1957 का अध्याय 5 अधिकारियों और नाविकों की सेवा की शर्तों से संबंधित है।धारा 14 में कहा गया है कि अधिकारी और नाविक भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना रिजर्व फोर्स में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जब तक कि उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती, बर्खास्त नहीं किया जाता, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, इस्तीफा

देने की अनुमति नहीं दी जाती या रिहा नहीं किया जाता।धारा 14 से 17 जिसका हाथ में मामले पर कुछ असर हो सकता है, इस प्रकार पढ़िएः

"14.अधिकारियों और नाविकों की सेवा के लिए दायित्व।-(1) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिकारी और नाविक भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना रिजर्व फोर्स में सेवा करने के लिए विश्वासयोग्य होंगे, जब तक कि उन्हें विधिवत छुट्टी नहीं दी जाती, अपमान के साथ बर्खास्त नहीं किया जाता, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जाती या रिहा नहीं किया जाता।

(2) केंद्र सरकार की अनुमति के अलावा कोई भी अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा और कोई भी नाविक निर्धारित अधिकारी की अनुमति के बिना अपने पद से इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

(3) किसी भी इस्तीफे की स्वीकृति केंद्र सरकार या संबंधित अधिकारी के विवेक के भीतर का मामला होगा।

(4) सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने की अनुमति प्राप्त अधिकारी इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार आपात स्थिति में नौसेना सेवा में वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी होंगे, और इस तरह के वापस बुलाए जाने पर वे तब तक सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक कि उन्हें विधिवत छुट्टी नहीं दी जाती, बर्खास्त नहीं किया जाता, बर्खास्त नहीं किया जाता, सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जाती या रिहा नहीं किया जाता।

15. अधिकारियों और नाविकों की सेवा का कार्यकाल।-(1) प्रत्येक अधिकारी और नाविक राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करेंगे। (2) इस अधिनियम और उसके अधीन विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए-(क) केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी या नाविक को नौसेना सेवा से बर्खास्त या बर्खास्त या सेवानिवृत्त कर सकती है; (ख) नौसेना प्रमुख या कोई निर्धारित अधिकारी किसी भी नाविक को नौसेना सेवा से बर्खास्त या खारिज़ सकता है।

16. सगाई की समाप्ति पर निर्वहन।-धारा 18 के प्रावधानों के अधीन, एक नाविक उस सेवा की अवधि की समाप्ति पर छुट्टी पाने का हकदार होगा जिसके लिए वह लगा हुआ है-

(ए) ऐसी समाप्ति सक्रिय सेवा के दौरान होती है जिसमें वह नौसेना प्रमुख द्वारा अपेक्षित ऐसी आगे की अवधि के लिए सेवा जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा; या (बी) वह इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार फिर से नामांकित है।

17. निर्वहन के संबंध में प्रावधान।-(I) धारा 16 के तहत आरोपित होने का हकदार नाविक को सभी सुविधाओं के साथ और किसी भी मामले में उसके इस तरह का हकदार बनने के एक महीने के भीतर छुट्टी दे दी जाएगीः

बशर्ते कि जहां कोई नाविक उस समय विदेश में सेवा कर रहा हो जब वह छुट्टी पाने का हकदार हो जाता है, तो उसे पूरी सुविधाजनक गति से छुट्टी दिए जाने के उद्देश्य से और किसी भी

मामले में उसके हकदार होने के तीन महीने के भीतर भारत वापस कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि जहां विदेशों में सेवा करने वाला ऐसा नामांकित व्यक्ति भारत लौटने की इच्छा नहीं रखता है, उसे उस स्थान पर छुट्टी दी जा सकती है जहां वह उस समय है।

(2) छुट्टी दिए गए प्रत्येक नाविक को भारत में किसी भी स्थान से, जहां वह उस समय हो सकता है, भारत में किसी भी स्थान पर, जहां वह उस समय हो सकता है, भारत में किसी भी स्थान पर, जहां वह जाना चाहता है, मुफ्त में पहुँचाने का अधिकार होगा।

(3) पूर्ववर्ती उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक नामांकित व्यक्ति तब तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी रहेगा जब तक कि उसे कम से कम छुट्टी नहीं दे दी जाती।

(4) प्रत्येक नाविक जिसे बर्खास्त किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, सेवानिवृत्त किया जाता है, इस्तीफा देने की अनुमति दी जाती है या सेवा से रिहा किया जाता है, निर्धारित अधिकारी द्वारा उस भाषा में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे नाविक की दूसरी भाषा है और अंग्रेजी भाषा में भी -

(क) उसकी सेवा समाप्त करने वाला प्राधिकारी;

((ख) ऐसी समाप्ति का कारण; और

(ग) भारतीय नौसेना और भारतीय नायल रिजर्व बलों में उनकी सेवा की पूरी अवधि।"

धारा 15 अधिकारियों और नाविकों के कार्यकाल के लिए प्रावधान करती है जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन हैं।1957 के अधिनियम के तहत सेवा की शर्तों के बारे में बनाए गए विनियम, सेवाओं की नौसेना औपचारिक शर्तें और विविध विनियम, 1964 हैं।विनियम 268 सभी प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों सहित संलग्नक से संबंधित है।विनियम 269 निरंतर सेवा से संबंधित है।विनियमन 269 प्रासंगिक समय पर लागू होता है जब 1973 से पहले आवेदकों की नियुक्ति की गई थी, जैसा कि 2010 के टी. ए.sankhya.492 में न्यायाधिकरण के निर्णय में निकाला गया था, इस प्रकार पढ़िएः

"विनियम 269:

निरंतर सेवा।(I) वृद्ध (प्रवेशक) लड़कों, कारीगर प्रशिक्षुओं और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफल समापन पर 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से या पुरुष (रैंक) में [रैंक] प्राप्त करने की तारीख से 10 वर्ष की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो, बशर्ते उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो।

सभी शाखाओं के निरंतर मेंवा नाविक, यदि आवश्यक हो, तो आगे की 10 वर्ष की मेंवा के लिए उत्तरदायी होंगे।भारतीय फ्लीट रिजर्व, भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधानों के अधीन।" (जोर दिया गया)

संशोधित विनियम 269 इस प्रकार हैः

"269 निरंतर सेवा।-[(1)पुराने [प्रवेशकर्ता] लड़कों, कारीगर प्रशिक्षुओं और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से या पुरुष [रैंक] में [रैंक] होने की तारीख से I0 वर्ष की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो।

सभी शाखाओं के निरंतर सेवा नाविक भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधानों के अधीन, यदि आवश्यक हो, तो भारतीय फ्लीट रिजर्व में एक और I0 वर्ष की सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

[(1ए.) नए प्रवेशक।-(क) लड़कों और प्रत्यक्ष प्रवेश नाविकों को नामांकन की तारीख से या 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से 15 वर्ष की सेवा की अवधि को पूरा करने की अनुमति देने के लिए गणना की गई अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, जो भी बाद में हो, बशर्ते उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो।] [(ए.ए.) कारीगर प्रशिक्षु और प्रत्यक्ष प्रवेश (डिप्लोमा धारक) कारीगरों को नामांकन की तारीख से या 17 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, 26 वर्ष की अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते उनकी सेवाओं की इतनी लंबी आवश्यकता हो।"]

(ख) 15 वर्ष या 20 वर्ष की प्रारंभिक नियुक्ति वाले सभी नए प्रवेशकों को, जैसा भी मामला हो, एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे

इस घोषणा से इस्तीफा देने के लिए विश्वसनीय होंगे कि वे गैर-कारीगरों के मामले में दो वर्ष और कारीगरों के मामले में तीन वर्ष तक की रिहाई के बाद सक्रिय सेवा वापस लेने के लिए उत्तरदायी होंगे।

बशर्ते कि उक्त अवधि के दौरान उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरने या किसी भी प्रतिधारण शुल्क के हकदार होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब उन्हें वापस बुलाया जाएगा तो वे सामान्य वेतन और भत्तों के हकदार होंगेः

बशर्ते कि यदि वापस बुलाया जाता है तो वे तब तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता हैः

बशर्ते कि अपने अनुरोध पर सेवा से समय से पहले रिहा किए गए साई टोर भी ऊपर बताई गई अवधि तक सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होंगे।

(1 बी)(ए) मौजूदा नाविकों के मामले में, उनके जुड़ाव की अवधि उप-विनियमन (1) द्वारा शासित होगी, सिवाय इसके कि उन्हें फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(ख) मौजूदा फ्लीट रिजर्विस्टों को प्रशिक्षण को कम करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वे तब तक पुनः प्रशिक्षण के हकदार होंगे जब तक कि वे बर्बाद नहीं हो जाते।

(1C) 3 जुलाई, 1976 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले व्यक्ति नए प्रवेशक माने जाएंगे।]

(2) किसी भी नाविक को तब तक फिर से नामांकित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता हैः-

(क) नामांकन से ठीक पहले के तीन वार्षिक मूल्यांकनों में से, उसके पास चरित्र और दक्षता के कम से कम दो मूल्यांकन होने चाहिए जो क्रमशः 'वी. जी.' और 'सत' से कम न हों।

(ख) अपने कप्तान द्वारा सेवा में बने रहने के लिए सभी मामलों में उपयुक्त होने की सिफारिश की जानी चाहिए।

(ग) उसे आवश्यक कर्तव्यों को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य घोषित किया गया होगा।"(जोर दिया गया)

नाविकों की सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विनियमन, विनियमन 279 है। यह निर्वहन प्रदान करता है।वही हमें पढ़ता हैः

"279.निर्वहन "एसएनएलआर".-(1) निर्वहन एसएनएलआर (सेवा की अब आवश्यकता नहीं है) को सजा के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि केवल समान की सेवाओं के वितरण का उचित तरीका माना जाएगाः

(क.) जो आवश्यकताओं से अधिशेष है,

(ख.) जिसका प्रतिधारण सेवा के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन जिसने हाल ही में कोई विशिष्ट अपराध नहीं किया है, जिसके लिए बर्खास्तगी किसी भी अन्य सजा के अलावा एक उचित सजा होगी।

(ग.) जिन पर नामांकन के बाद सत्यापन रिपोर्ट में एक प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी गई है।

(2) उप-विनियमन (I) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि किसी नाविक के प्रतिधारण को आचरण या चरित्र के आधार पर अवांछनीय माना जाता है, तो उसके सेवा दस्तावेजों के साथ एक रिपोर्ट प्रशासनिक प्राधिकरण को भेजी जाएगी, जिसमें सिफारिश की जाएगी कि उस व्यक्ति को 'सेवा की आवश्यकता नहीं है'।(3) नाविकों को सेवा के रूप में निर्वहन के लिए सिफारिशों के सभी मामलों में जिनकी अब आवश्यकता

नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें आवश्यकताओं के अतिरिक्त के रूप में अधिभारित किया जाना है, कप्तान इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे कि नाविक।छुट्टी के लिए अनुशंसित को उपयुक्त चेतावनी और सुधार का अवसर दिया गया है।इस प्रभाव का प्रमाण सिफारिश के साथ होगा।असाधारण मामलों में जब कप्तान की राय में एक नाविक का प्रतिधारण स्पष्ट रूप से अवांछनीय है, तो एक सिफारिश अग्रेषित की जा सकती है और निर्वहन को मंजूरी दी जा सकती है, हालांकि नाविक को पहले चेतावनी नहीं दी गई है।

(4) यदि प्रशासनिक प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि 'द्वारावा की अधिक समय तक आवश्यकता नहीं' उचित है, तो वह कैप्टन नेवल बैरक के माध्यम द्वारा नौद्वाराना प्रमुख को उनकी सिफारिश के साथ आवेदन भेजेगा।यह आवश्यक है।व्यक्ति के सेवा दस्तावेजों को अप-टू-डेट पूरा किया जाना निर्वहन के लिए आवेदन के साथ होगा।

(5) विदेश में, 'सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड' के लिए अनुशंसित नाविकों को तब तक घर नहीं भेजा जाएगा जब तक कि नौसेना प्रमुख की छुट्टी के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती।यदि अंतरिम में, उस व्यक्ति को दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ भेजे गए सेवा दस्तावेज को इस प्रभाव से टिप्पणी की जाएगी कि उसके निर्वहन के लिए एक आवेदन किया गया है और आवेदन की एक प्रति उसके कागजात के साथ होगी।"

वास्तव में, सेवा की अवधि समाप्त होने से पहले निर्वहन के लिए प्रावधान करने वाले विनियमन 279 को लागू किया जा सकता है।।

10. इन विनियमों के अलावा, अब हम नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 के रूप में जाने जाने वाले 1957 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

बनाए गए पेंशन विनियमों का विज्ञापन करेंगे।विनियमन 92 रिजर्विस्ट पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित है जो इस प्रकार हैः

"92.आरक्षित पेंशन और उपदान।•(I) एक आरक्षित व्यक्ति जो सेवा पेंशन की प्राप्ति में नहीं है, उसे निर्धारित नौसेना और आरक्षित योग्यता सेवा के पूरा होने पर, आमतौर पर हर साल, ग्यारह रुपये प्रति माह की आरक्षित पेंशन या पेंशन के बदले नौ सौ रुपये की उपदान दी जा सकती है।

(2) एक आरक्षित व्यक्ति जो सेवा पेंशन की प्राप्ति में नहीं है और जिसकी योग्यता सेवा सगाई की अवधि से कम नहीं है, लेकिन पंद्रह साल से कम नहीं है, उसे अनुबंध की अवधि पूरी होने पर या अपने अनुरोध पर अन्य आरक्षित से पहले निर्वहन पर, प्रति वर्ष रुपये की दर से आरक्षित पेंशन या पेंशन के बदले सात सौ पचास रुपये की उपदान दी जा सकती है।

(3) जहां कोई आरक्षित व्यक्ति इस विनियमन के तहत पेंशन के बदले उपदान प्राप्त करने का चुनाव करता है, तो उपदान की राशि किसी भी मामले में उस सेवा उपदान से कम नहीं होगी जो उसे भारतीय नौसेना में योग्यता सेवा के आधार पर विनियमन 89 के तहत अर्जित होती, अगर उसे सक्रिय सूची से छुट्टी दे दी जाती। स्पष्टीकरण।- विकल्प-पेंशन के बदले उपदान प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग रिजर्व से निर्वहन में किया जाएगा, और एक बार उपयोग किए जाने के बाद विकल्प अंतिम होगा; जब तक विकल्प का उपयोग

नहीं किया जाता है, तब तक कोई पेंशन या उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा।"

विनियम 95 नाविकों के लिए विशेष पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

"95.नाविकों के लिए विशेष पेंशन और उपदान-जब स्वीकार्य हो।-केंद्र सरकार के विवेक पर उन नाविकों को विशेष पेंशन या उपदान दिया जा सकता है जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया जाता है और जिन्हें सरकार की नीति-I के अनुसार बड़ी संख्या में छुट्टी दी जाती है।भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को कम करना।पुनर्गठन, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी जहाज के पुनर्स्थापन का भुगतान किया जाता है।"

भारतीय नौसेना रिजर्व बल (अनुशासन) अधिनियम, 1939 के तहत बनाए गए भारतीय फ्लीट रिजर्व के विनियमों का विनियम 6 इस प्रकार हैः

"6.फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का दावा-कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में फ्लीट रिजर्व में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है।"

पुन: आरक्षित पेंशन

11. हम सबसे पहले आरक्षित पेंशन का दावा करने की पात्रता के बारे में प्रश्न पर विचार करेंगे।विनियमन 92 का उपखंड (I) इस पहलू पर कुछ प्रकाश डालता है।यह प्रावधान करता है कि एक "आरक्षित" जो सेवा पेंशन की प्राप्ति में नहीं है, उसे प्रत्येक 10 वर्ष की निर्धारित नौसेना और आरक्षित सेवा के पूरा होने पर आरक्षित पेंशन दी जाएगी।न तो कोई भी आवेदक यह दावा करता है कि वे सेवा पेंशन के हकदार हैं और न ही उन्हें ऐसा दिया गया है।आरक्षित पेंशन के लिए अनुदान की पात्रता 10-10

वर्ष की निर्धारित नौसेना और आरक्षित योग्यता सेवा के पूरा होने पर है।यह विवाद में नहीं है कि प्रत्येक आवेदक ने पहली बार में 10 साल की निर्धारित नौसेना सेवा पूरी की, जिसे सक्रिय सेवा या जुड़ाव भी कहा जाता है।यह भी विवाद में नहीं है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहली बार में 10 साल की सक्रिय सेवा पूरी करने के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में संबंधित आवेदक की सेवाओं का मसौदा तैयार करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

12. वास्तव में विचाराधीन मुद्दा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली, टी. ए. संख्या.492/2009 के समक्ष विषय था।न्यायाधिकरण ने प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "9.यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को फ्लीट रिजर्व सर्विस के लिए शामिल नहीं किया गया था।उन्होंने रिकॉर्ड और सेवा प्रमाण पत्र पर अपनी सेवा का एक निर्वहन प्रमाण पत्र और प्रोफाइल दाखिल किया है जो यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता अल । में फ्लीट रिजर्व सर्विस के लिए लगा हुआ था या नहीं।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब उन्होंने उस समय सेवा में प्रवेश किया तो नियम के अनुसार 10 वर्ष की नियमित सेवा और I0 वर्ष की बेड़ा आरक्षित सेवा और उस पाँच वर्ष की सेवा को पेंशन के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए।यह प्रासंगिक समय पर सच है जब याचिकाकर्ता को सेवा में शामिल किया गया था, तो पदधारी को बेड़ा आरक्षित में रखने की आवश्यकता थी, इसलिए, उत्तरदाता उस समय प्रचलित सेवा शर्तों से बाध्य हैं और उन्हें बेड़ा आरक्षित सेवा का 5 साल का लाभ देना चाहिए।यह सच है कि हमने निश्चित रूप से अनुरोध को स्वीकार कर

लिया होगा, लेकिन एक कठिनाई उत्पन्न हुई कि विनियमन 269 स्पष्ट रूप से विचार करता है कि यदि आवश्यक हो तो आरक्षित बेड़े के लिए मौजूदा रखा जा सकता है।फ्लीट रिजर्व में रखने की सरकार की इस नीति को वर्ष 1976 में बंद कर दिया गया था।विनियम 269 स्पष्ट रूप से इस बात पर विचार करता है कि यदि आवश्यक हो तो इनकम्बेंट को फ्लीट रिजर्व में रखा जा सकता है, इसका मतलब है कि यह प्रत्यर्थीगण को फ्लीट रिजर्व में इनकम्बेंट रखने की स्वतंत्रता देने वाले प्रावधान को सक्षम कर रहा है, यह याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है कि उसे अनिवार्य रूप से फ्लीट रिजर्व में रखा जाना चाहिए।यह प्रत्यर्थीगण का विवेकाधिकार है कि यदि उन्हें आवश्यकता होती है, तो वे लोगों को बेड़ा आरक्षित में रखते हैं और यदि उन्हें पता चलता है कि उन्हें बेड़ा आरक्षित के लिए परमादेश की आवश्यकता नहीं है, तो परमादेश अधिकार के रूप में अनिवार्य रिट की मांग नहीं कर सकता है, उसे बेड़ा आरक्षित में रखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।"यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है कि फ्लीट रिजर्व में पदधारी को रखने या न रखने का विवेकाधिकार प्रत्यर्थीगण के पास है।चूंकि यह नीति 1976 में जारी रही है, इसलिए अब से बेड़े को आरक्षित रखने का कोई प्रावधान नहीं है।याचिकाकर्ता को वर्ष 1978 में आरोप मुक्त कर दिया गया था।वह उस समय के प्रावधान को भी जानते थे कि उन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया है।इसलिए, याचिकाकर्ता को 1 वर्ष की फ्लीट रिजर्व सेवा में से 5 वर्ष की सेवा का लाभ नहीं मिल सकता है ताकि पेंशन के लिए 15 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी की जा सके।

13. न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को इस अदालत के समक्ष एसएलपी (सिविल) क्रमांक 19790/2010 जिसे, हालाँकि,13 जनवरी 2014 को खारिज कर दिया गया था।उक्त आदेश इस प्रकार हैः

> "सुना है।हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी अनुमति ।
>
> हालाँकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश याचिकाकर्ता को नौसेना (पेंशन) विनियमन, एफ 964 के विनियमन 95 के संदर्भ में विशेष पेंशन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी को उचित प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोकेगा।
>
> श्री मोहन जैन, विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करते हैं कि यदि ऐसी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच की जाएगी और कानून में अनुसार उचित आदेश किए जाएंगे।यह कथन दर्ज किया गया है।
>
> हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस दावे के गुण -दोष के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है कि याचिकाकर्ता विशेष पेंशन के भुगतान के लिए प्रस्ताव करता है।यह मामला कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम प्राधिकारी में छोड़ दिया गया है।यदि सक्षम प्राधिकारी इस विषय पर प्रतिकूल दृष्टिकोण रखता है, तो याचिकाकर्ता को उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही में इसके खिलाफ निवारण की मांग करने की स्वतंत्रता होगी।कोई लागत नहीं।"

14. विभाग द्वारा यह न्यायोचित रूप से तर्क दिया जाता है कि न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय की इस अदालत द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, इसके विपरीत

विवादित निर्णय में न्यायाधिकरण की राय को निहित रूप से खारिज किया जा सकता है।फिर भी, हम विवादित निर्णय में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

15. सक्षम प्राधिकरण के स्पष्ट आदेश की अनुपस्थिति में में फ्लीट रिजर्व सेवा पर आवेदकों को शामिल करने के लिए, मुख्य प्रश्न हैःक्या नियुक्ति पत्र में दी गई शर्त के कारण आवेदकों को फ्लीट रिजर्व सेवा में माना जा सकता है-कि नाविक के रूप में नौसेना सेवा के 10 वर्ष पूरे होने पर, उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए फ्लीट रिजर्व सेवा में रहना होगा।नियुक्ति पत्र में उस शर्त को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।नाविकों की शासकीय कार्य स्थितियों का पता 1957 के अधिनियम के प्रावधानों या संबंधित सेवा शर्तों के तहत बनाए गए विनियमों से लगाया जाना चाहिए।1957 के अधिनियम के प्रावधानों से यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि नियुक्ति या नामांकन के बाद नाविक 10 साल की प्रारंभिक, सक्रिय सेवा अवधि पूरी होने के बाद स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहने का हकदार है।हालांकि, प्रावधानों से संकेत मिलता है कि 10 साल की प्रारंभिक सक्रिय सेवा पूरी होने पर या संशोधित प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई अवधि अधिनियम की धारा 16 के संदर्भ में निर्वहन लेने का हकदार है। आवेदकों का कहना है कि किसी भी आवेदक ने छुट्टी का विकल्प नहीं चुना।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक नाविक के रूप में सक्रिय सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में रहेंगे या वास्तव में बने रहेंगे।संबंधित आवेदक फ्लीट रिजर्व सर्विस का सौदा तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा एक एक्सप्रेस ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए था।इस तरह के आदेश की अनुपस्थिति में में, नियुक्ति की सेवा की अवधि पूरी होने पर, संबंधित नाविक को छुट्टी दे दी जाएगी।स्वीकार्य रूप से, फ्लीट रिजर्व सेवा पर प्रतिधारण नियोक्ता के लिए अनिवार्य है, जिसका उपयोग मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में एक नीतिगत

निर्णय के कारण, 3 जुलाई 1976 की अधिसूचना के संदर्भ में फ्लीट रिजर्व सेवा को बंद कर दिया गया था।उक्त अधिसूचना इस प्रकार हैः

"नंबर एडी/5374/2/76/2214/एस/डी (एन.11),

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय;

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1976

को,

नौसेना प्रमुख (100 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)

उपः- नाविकों की सेवा की शर्तें।

महोदय, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति ने नाविकों की सेवा की शर्तों में निम्नलिखित संशोधनों को मंजूरी दी हैः-

क) घटना की प्रारंभिक अवधिः- 15 साल के लिए प्रवेश करें।

ख) प्रवेश में शैक्षिक योग्यता:- सीमैन और मरीन इंजीनियरिंग शाखाओं के डायरेक्ट एंट्री नाविकों और सभी शाखाओं के बो एंट्री नाविकों के मामले में मैट्रिक या समकक्ष तक उठाया जाए।

ग) प्रवेश की आयु :- लड़कों के लिए प्रवेश की आयु को संशोधित करके 16-18 वर्ष और सीधे प्रवेश करने वाले नाविकों के लिए 18-20 वर्ष कर दिया जाए।

घ) सेवानिवृत्ति की अनिवार्य आयुः- निर्धारित नियमों के अधीन, सी. पी. ओ. रैंक सहित सभी रैंकों के नाविकों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष होगी।एम. सी. पी. ओ. I/II की अनिवार्य सेवानिवृत्ति 55 वर्ष रहेगी।

ई) अग्रणी रैंक के लिए समय पैमाने पर पदोन्नतिः- नाविक प्रथम श्रेणी और समकक्षों को निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन पुरुष रैंक में 5 साल की सेवा पूरी करने पर

अग्रणी रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा।इस प्रावधान के कार्यान्वयन की तारीख नौसेना मुख्यालय द्वारा घोषित की जाएगी।

टी) वर्तमान फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरणः- फ्लीट रिजर्व में नाविकों का स्थानांतरण बंद किया जाएगा।मौजूदा फ्लीट रिजर्विस्टों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें तब तक मुफ्त में रखा जाएगा जब तक कि वे बर्बाद नहीं हो जाते।

छ) सक्रिय सेवा को याद करनाः- (i) 15 साल की प्रारंभिक नियुक्ति के साथ सभी नए प्रवेशकर्ता और ऐसे मौजूदा नाविक, जो न्यूनतम पेंशन के लिए पूरा समय लेने के लिए फिर से जुड़ते हैं, एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए कि वे गैर-कलाकारों के मामले में दो साल और कलाकारों के मामले में तीन साल की रिहाई के बाद सक्रिय सेवा के लिए वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।इस अवधि के दौरान उन्हें प्रशिक्षण को कम करने या किसी भी पुनः प्रशिक्षण शुल्क के हकदार होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब उन्हें वापस लिया जाएगा तो वे सामान्य वेतन और भत्तों के हकदार होंगे। यदि वापस लिया जाता है तो वे तब तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे जब तक कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

(ii) अपने अनुरोध पर सेवा से समय से पहले रिहा किए गए नाविक भी ऊपर बताई गई अवधि तक सक्रिय सेवा के लिए वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

ज) नाविकों का पुनर्गठन और निष्कासनः- सीमेन और एम. ई. शाखाओं में भविष्य में प्रवेश करने वाले (बॉय और डायरेक्ट एंट्री दोनों) वेतन के समूह 'बी' पैमाने पर होंगे। विनियामक शाखा सहित इन शाखाओं में सेवारत नाविक, जो मैट्रिक या समकक्ष हैं, उन्हें भी 1 अप्रैल, 1976 से समूह "बी" पैमाने पर वेतन दिया जाएगा।जो लोग बाद में इस योग्यता को प्राप्त करते हैं, उन्हें अर्हता प्राप्त करने पर वेतन के समूह 'बी' पैमाने

पर भी नियुक्त किया जाएगा।रिमस्टरिंग निश्चित रूप से उस महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगी जिसमें यह होता है।

2. प्रशासनिक निर्देश, यदि कोई हों, तो नौसेना मुख्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. उचित सरकारी विनियमों/आदेशों में नियत समय में संशोधन किया जाएगा।4.यह वित्त मंत्रालय (डेफ) की सहमति से उनके यू. ओ. 1976 वाद प्रश्न संख्या.452/NA/S

आपकी वफादारी से,

एस. डी./- (पी. एस. अहलूवालिया)

भारत सरकार के अवर सचिव

16. इस नीति के अनुसार, जुड़ाव की प्रारंभिक अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था।उसी समय नाविकों का फ्लीट रिजर्व में स्थानांतरण बंद कर दिया गया था।यह नीति के खंड (टी) में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। इसी खंड का दूसरा भाग "मौजूदा फ्लीट रिजर्विस्ट" से संबंधित है," जिन्हें तब तक प्रतिधारण शुल्क का भुगतान किया जाना था जब तक कि वे बर्बाद नहीं हो जाते।

17. जैसा कि अब तक उल्लेख किया गया है, प्रासंगिक प्रावधानों में से कोई भी दूर से यह सुझाव नहीं देता है कि नाविक को "स्वचालित रूप से" फ्लीट रिजर्व सर्विस में स्थानांतरित कर दिया गया है।जबकि, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अनुबंध की सेवा की अवधि समाप्त होने में नाविक को फ्लीट रिजर्व सर्विस में केवल तभी रखा जाएगा जब सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसे फ्लीट रिजर्व में मसौदा तैयार करने के लिए एक स्पष्ट आदेश किया जाता है और अन्यथा नहीं।अधिनियम की धारा 16, केवल नाविक को नियुक्ति की सेवा की अवधि समाप्त होने के बाद छुट्टी लेने का विकल्प देती है।यह एक ऐसा प्रावधान नहीं है कि यदि संबंधित नाविक द्वारा इस तरह

के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसे अगले कुछ वर्षों के लिए स्वचालित रूप से फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल किया गया माना जाएगा।

18. विनियम 269 में सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है।यह इस स्थिति को मजबूत करता है कि एक नाविक की सेवाओं को "इतने लंबे समय तक आवश्यक" या "यदि आवश्यक हो" जारी रखा जाएगा।उस विनियमन के खंड (I) के दूसरे भाग में भारतीय फ्लीट रिजर्व के लिए विनियमों के प्रावधानों के अधीन, भारतीय फ्लीट रिजर्व में आगे की 10 वर्षों की सेवा के लिए "यदि आवश्यक हो" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। 2009 के टी. ए. sankhya.492 में न्यायाधिकरण (प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली) द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण हमारे लिए सराहनीय है।

19. जैसा कि ऊपर कहा गया है, 3 जुलाई, 1976 को नई नीति शुरू करने पर, फ्लीट रिजर्व को बंद कर दिया गया था और इसके बजाय बी. प्रासंगिक समय पर सेवा में नाविकों को 5 साल की अगली अवधि के लिए सक्रिय सेवा में बने रहने का विकल्प दिया गया था।कुछ नाविकों ने 15 साल पूरे होने तक जारी रखने का विकल्प चुना, जो तब योग्यता सेवा के साथ "सेवा पेंशन" के लिए पात्र हो गए।

20. विनियमन 92 के अनुसार, आरक्षित पेंशन के अनुदान का सार, प्रत्येक जे. ओ. वर्ष की निर्धारित नौसेना और आरक्षित योग्यता सेवा को पूरा करना है।केवल एक नाविक के रूप में सक्रिय सेवा के जॉयर्स के पूरा होने पर या उस मामले के लिए उस अवधि के बाद भी जारी रहा, लेकिन 15 साल या आरक्षित सेवा की योग्यता से कम होने पर, संबंधित नाविक आरक्षित पेंशन के अनुदान के लिए विनियमन 92 के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।क्योंकि, रिजर्विस्ट पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व सर्विस में शामिल किया जाना चाहिए।भारतीय बेड़ा आरक्षित विनियमों के विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार,

अधिकार के रूप में बेड़ा आरक्षित में शामिल होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है।सक्रिय सेवा पूरी करने के बाद किसी भी आवेदक को फ्लीट रिजर्व सेवा में शामिल नहीं किया गया था।इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदक, आरक्षित पेंशन की राहत का दावा नहीं कर सकते थे।हालाँकि, न्यायाधिकरण (क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई) क्रमांक 2013 के ओ. ए. संख्या 83 में आवेदकों पक्ष में न्यायसंगत वचन बहिष्कार और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके उस राहत को प्रदान किया।न्यायाधिकरण ने, हमारी राय में 1957 के अधिनियम में वैधानिक प्रावधानों और नाविकों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों की अनदेखी करने में स्पष्ट त्रुटि की।यह तथ्य कि 0 वर्ष की सक्रिय सेवा के पूरा होने पर, नाविक को 10 वर्ष की आगे की अवधि के लिए फ्लीट रिजर्व सर्विस पर ले जाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि संबंधित नाविक ने फ्लीट रिजर्व सर्विस में शामिल होने का कानूनी अधिकार हासिल कर लिया था या सक्रिय सेवा/जुड़ाव की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद डी ज्यूरे ने फ्लीट रिजर्व सर्विस पर 10 साल तक काम करना जारी रखा था।1957 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह सुझाव दे सके कि फ्लीट रिजर्व सेवा पर ऐसे नाविकों का मसौदा तैयार करना उनकी सक्रिय सेवा/नामांकन अवधि की समाप्ति के बाद "स्वचालित" था।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायसंगत प्रतिदावा रोक और वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए निर्णयों के साथ इस निर्णय को बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है, जो वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होते हैं।

21. मूल आवेदकों का तर्क है कि यदि 3 जुलाई, 1976 की सरकारी नीति सेवारत नाविकों पर लागू होती है, तो अनिवार्य रूप से, उनके निर्णय के लिए इसका पूर्वव्यापी अनुप्रयोग होगा।यह अधिनियम की धारा 184-ए द्वारा निषिद्ध है। यह तर्क

हमें स्वीकार्य नहीं है।अर्थात्, सरकारी नीति का प्रभाव 3 जुलाई, 1976 से रिजर्व फ्लीट सर्विस की स्थापना को भंग करना है। शुरुआत में, रिजर्व फ्लीट सर्विस में नाविकों का मसौदा तैयार करना स्वचालित नहीं था, बल्कि यह मामले-दर-मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले एक स्पष्ट आदेश पर निर्भर था। नाविकों के पास रिजर्व फ्लीट सर्विस में रखे जाने का कोई निहित अधिकार नहीं था। इसलिए, 3 जुलाई, 1976 की नीति के कारण सक्रिय सेवा में साई आईअर्स का कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं हुआ या छीन लिया गया। यहां तक कि मूल आवेदकों का तर्क भी है कि विनियमन 269 (1) में होने वाली अभिव्यक्ति "यदि आवश्यक हो" की व्याख्या असमान सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करती है। सरकार गुणहीन है. । विनियमन 269 (1) की वैधता में न्यायाधिकरण के समक्ष सवाल नहीं उठाया गया था और न ही उस ओर से किसी राहत का दावा किया गया था।इसलिए, यह तर्क मूल आवेदकों के लिए अनुपलब्ध है।किसी भी मामले में, नाविकों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को एक साथ पढ़ने पर और विशेष रूप से यह ध्यान देने पर कि नाविकों को फ्लीट रिजर्व सेवा में रखना सरकार का विशेषाधिकार है; और साथ ही नाविकों को अधिनियम की धारा 16 की शर्तों के अनुसार छुट्टी का विकल्प दिया गया था, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इस तरह के वितरण को असमान सौदेबाजी शक्ति कैसे कहा जा सकता है।संबंधित नाविक को फ्लीट रिजर्व सर्विस में नहीं रखने के परिणामस्वरूप सेवा निवृत्ति वेतन से वंचित किया जा सकता है।हालाँकि, मूल आवेदक पेंशन विनियमों के विनियम 95 के तहत विशेष पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं, जो ऐसे नाविकों के लिए एक अलग व्यवस्था है, जब तक कि विनियम 279 के तहत सजा के रूप में छुट्टी नहीं दी जाती है।

22. तदनुसार, हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई भी आवेदक नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 के विनियम 92 के संदर्भ में आरक्षित पेंशन का हकदार नहीं

है।न्यायाधिकरण ने उसी न्यायाधिकरण की अन्य पीठों के अन्य निर्णयों पर भरोसा किया है, जिन्हें उसी कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पुन: विशेष पेंशन

23. अगला प्रश्न यह है कि क्या 1973 से पहले नियुक्त नाविक पेंशन विनियमों के विनियम 95 के संदर्भ में विशेष पेंशन के हकदार थे।वास्तव में, यह एक विशेष प्रावधान है और नाविकों की श्रेणी तैयार करता है, जिन पर यह लागू होना चाहिए।ऐसे नाविकों को विशेष पेंशन देने का विवेकाधिकार केंद्र सरकार में निहित है, जो अपवाद श्रेणी में आते हैं।विनियम 95 में दो व्यापक अपवादित श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।पहला, नाविक जिन्हें भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत को कम करने की सरकारी नीति के अनुसरण में अपने कर्तव्यों से छुट्टी दे दी गई है; या दूसरा, पुनर्गठन, जिसका परिणाम किसी भी जहाज या प्रतिष्ठान को भुगतान करने में होता है।वर्तमान मामले में 3 जुलाई, 1976 की अधिसूचना में सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की पृष्ठभूमि में विनियमन 95 एमयू1 एनटी का खंड (i) लागू होता है। उस तारीख को और उसके बाद से, निश्चित रूप से, फ्लीट रिजर्व सर्विस को बंद कर दिया गया है।यह अनिवार्य रूप में उक्त नीति के लागू होने के बाद भारतीय नौमेंना के फ्लीट रिजर्व की स्थापना की ताकत को उस हद तक कम कर देता है।उक्त नीति के लागू होने के बाद किसी भी नाविक को फ्लीट रिजर्व में शामिल नहीं किया गया था या नहीं किया जा सका था-क्योंकि वह प्रतिष्ठान अब मौजूद नहीं था और भारतीय नौसेना की स्थापना की ताकत कम हो गई थी।निर्विवाद रूप से, 3 जुलाई, 1976 से पहले नियुक्त नाविकों के पास अपनी सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि की समाप्ति के बाद फ्लीट रिजर्व सेवा में बने रहने का विकल्प था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्येक आवेदक के संबंध में नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि का उल्लेख प्रारंभिक सक्रिय सेवा के 1 वर्ष और फिर 1 वर्ष, यदि आवश्यक हो, तो फ्लीट रिजर्व सेवा के रूप

में किया गया है।फ्लीट रिजर्व सर्विस पर बने रहने का विकल्प इन आवेदकों और इसी तरह से तैनात नाविकों को विभाग द्वारा, उनकी सूची में शामिल करने की अवधि I 0 वर्ष या आईएस वर्ष से कम की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, पेश नहीं किया जा सका।यही कारण है कि ऐसे नाविकों को उनकी सक्रिय सेवा/सूची अवधि की समाप्ति पर छुट्टी दे दी गई थी।दूसरे शब्दों में, 3 जुलाई, 1976 की नीति के अनुसार, भारतीय नौसेना के फ्लीट रिजर्व प्रतिष्ठान को बंद करने के कारण।इसने भारतीय नौमेंना की स्थापना की ताकत को उस हद तक कम कर दिया है।

24. यह हमें अपीलर्थी संख्या.36 (सीए संख्या.2147/2011 में) के मामले में ले जाता है।उक्त अपीलकर्ता दावा करता है कि उसे विभाग द्वारा एकतरफा रूप से फ्लीट रिजर्व से छुट्टी दे दी गई थी।उस समय तक, उन्होंने संयुक्त रूप से 17 साल पहले महीने और 26 दिनों की सेवा पूरी कर ली थी, जिसके लिए वे पेंशन विनियमों के विनियम 92 (2) के तहत आरक्षित पेंशन के हकदार थे।उक्त अपीलकर्ता इस तर्क के समर्थन में 81 मई, 2014 के संचार पर भरोसा कर रहा है।चूंकि यह अपीलार्थी 3 जुलाई, 1976 की सरकारी नीति के अस्तित्व में आने के समय सक्रिय सेवा में नहीं था और 30 से 1 मार्च, 1967 को फ्लीट सर्विस से छुट्टी मिलने का दावा करता है, इसलिए वह सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र होगा।यह सक्षम प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी है कि क्या निर्वहन एकतरफा था और उक्त अपीलकर्ता के प्रश्न पर नहीं था और इसमें यह भी शामिल है कि क्या वह पेंशन विनियमन के विनियमन 92 (2) के संदर्भ में आरक्षित पेंशन का हकदार होगा।यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने उन प्रश्नों के संबंध में कोई राय व्यक्त की है जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

25. इस प्रकार समझा जाता है कि 3 जुलाई, 1976 से पहले नियुक्त किए गए सभी नाविक और जिनका प्रारंभिक सक्रिय सेवा/सूचीकरण अवधि 3 जुलाई, 1976 को

या उसके बाद समाप्त हो गई है, वे विनियमन 95 के तहत विशेष पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते कि वे अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।इसमें, उन्होंने अनुबंध की समाप्ति (1957 के अधिनियम की धारा 16 के अनुसार) पर निर्वहन लेने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और फिर भी फ्लीट रिजर्व सेवा को बंद करने की नीति के कारण फ्लीट रिजर्व के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा मसौदा तैयार नहीं किया गया था और न ही किया जा सका था।ऐसे नाविकों (न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदकों तक सीमित नहीं) के मामलों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित नाविक द्वारा आवेदन की तारीख से तीन साल पहले से "विशेष पेंशन" देने के लिए तीन महीने के भीतर विचार किया जाना चाहिए और अवशिष्ट राशि से उन्हें पहले से ही भुगतान किए गए ग्रेच्युटी और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-ग्रेच्युटी (डी. सी. आर. जी.) का समायोजन करने के बाद भुगतान जारी किया जाना चाहिए।वे भुगतान की तारीख तक अवशिष्ट पर 9 प्रतिशत पी. ए. की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

26. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में बिना किसी आदेश के किया जाता है। अभियोग लगाने के आवेदन का भी निपटारा कर दिया जाता है।

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावाहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।